ग्वालियर | गुरुवार | 10 जुलाई 2025 | वर्ष 30 | अंक 152 | पृष्ठ 12 | मूल्य रु. 5.00
navabharat.com twitter.com/Nava_Bharat fb.me/NavaBharat.Social

नव भारत
राष्ट्र हित का प्रहरी 1938 से

एक नजर में

भारत की सुरक्षा पर मंडरा रहा नया खतरा : सीडीएस

नई दिल्ली. भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने नयी दिल्ली स्थित एक थिंक-टैंक संस्था सेंटर फॉर जॉइंट वारफेयर स्टडीज (सीईएनजेओडब्लूएस) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भारत की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि अगर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच किसी प्रकार का रणनीतिक गठजोड़ होता है, तो यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन सकता है. जनरल चौहान ने कहा कि इन तीनों देशों के साझा हित भारत को चारों ओर से घेरने की दिशा में बढ़ सकते हैं. खासतौर पर जब बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता है और प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी है, तो यह स्थिति और अधिक संवेदनशील हो जाती है.

युद्धपोत 'निस्तार' नौसेना में शामिल

नयी दिल्ली. गहरे समुद्र में गोताखोरी तथा बचाव अभियान चलाने में सक्षम स्वदेशी युद्धपोत निस्तार नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया है. देश की प्रमुख शिपयार्ड कंपनी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने मंगलवार को विशाखापत्तनम में नौसेना को यह युद्धपोत सौंपा. इस युद्धपोत को भारतीय नौवहन के अनुसार डिज़ाइन और निर्मित किया गया है और यह गहरे समुद्र में गोताखोरी तथा बचाव अभियान चला सकता है. इसके साथ ही भारतीय नौसेना यह क्षमता हासिल करने वाली दुनिया की चुनिंदा नौसेनाओं में शामिल हो गयी है. इस युद्धपोत का नाम 'निस्तार' संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ मुक्ति, बचाव या मोक्ष है. निस्तार 118 मीटर लंबा है और लगभग दस हजार टन भार वाले इस युद्धपोत में अत्याधुनिक गोताखोरी उपकरण लगे हैं.

जगुआर दुर्घटनाग्रस्त दोनों पायलट की मौत

नयी दिल्ली. भारतीय वायुसेना का एक जगुआर ट्रेनर विमान बुधवार दोपहर राजस्थान के चुरू के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, दुर्घटना में दोनों पायलट की मौत हो गयी. वायु सेना ने कहा है कि यह विमान नियमित प्रशिक्षण उडान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. दुर्घटना में दोनों पायलट की मौत हो गयी. दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की गई है. वायु सेना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा, भारतीय वायुसेना का एक जगुआर ट्रेनर विमान आज राजस्थान के चुरू के पास नियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस दुर्घटना में दोनों पायलटों की मौत हो गयी. किसी भी नागरिक संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है. भारतीय वायुसेना इस दुखद घटना पर गहरा दुःख व्यक्त करती है और इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ी है.

गुस्ताखी माफ

मोदी को सर्वोच्च सम्मान

नामीबिया और भारत के बीच हुए दो समझौतों पर हस्ताक्षर

विंडहोक / नयी दिल्ली 09 जुलाई. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नामीबिया की राष्ट्रपति डॉ. नेटुम्बो नंदी-नदैतवा ने द्विपक्षीय व्यापार की संभावनाओं का अधिक से अधिक दोहन करने के लिए तरजीही व्यापार समझौते पर चर्चा को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने पर सहमति व्यक्त की है. यह नामीबिया में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की तीसरी और मोदी की पहली यात्रा है.

दोनों देशों ने स्वास्थ्य और उद्यमिता के क्षेत्र में दो समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए हैं. इसके अलावा नामीबिया के आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने की भी घोषणा की गई. साथ ही नामीबिया भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बन गया. पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में बुधवार को यहां पहुंचे मोदी ने स्टेट हाउस में राष्ट्रपति नेटुम्बो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की. दोनों नेताओं ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी और यूपीआई, कृषि, स्वास्थ्य एवं फार्मा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय संबंधों को और मज़बूत करने पर चर्चा की. द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस मोर्चे पर अभी भी क्षमता का दोहन किया जाना बाकी है. इस संबंध में, उन्होंने भारत-एसएसीयू तरजीही व्यापार समझौते पर चर्चा में तेजी लाने का आह्वान किया.

भारत और ब्राजील के बीच तीन प्रमुख समझौते

1. आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने में सहयोग
2. वर्गीकृत सूचनाओं का आदान-प्रदान और पारस्परिक संरक्षण.
3. नागरिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता.

'ऑर्डर ऑफ़ द मोस्ट एन्शिएंट पेल्वित्शिया मिराबिलिस' नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है. डॉ. नेटुम्बो ने पुरस्कार प्रदान करने से पहले कहा, नामीबियाई संविधान द्वारा मुझे प्रदत्त शक्ति के द्वारा मुझे भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एन्शियेंट वेल्वित्चिया मिराबिलिस प्रदान करने का सम्मान प्राप्त हुआ है, जिन्होंने नामीबिया और विश्व स्तर पर सामाजिक-आर्थिक विकास तथा शांति और न्याय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. मोदी ने सम्मानित किये जाने के बाद कहा, वेल्वित्स्चिया मिराबिलिस से सम्मानित होना मेरे लिए अत्यंत गौरव और सम्मान की बात है. मैं राष्ट्रपति, नामीबिया सरकार और नामीबिया की जनता के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ. मैं 140 करोड़ भारतीयों की ओर से इस सम्मान को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूँ.

49263 नये नियमित पदों पर भर्ती

- कैबिनेट ने बिजली कंपनियों के लिए इन पदों की दे दी मंजूरी
- 35 लाख किसानों की सिंचाई जलकर किया माफ

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 9 जुलाई. लंबे समय से अधिकारियों- कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे प्रदेश की सभी 6 बिजली कंपनियों को 49263 नये अधिकारी-कर्मचारी मिलेंगे. कैबिनेट ने बुधवार को बिजली कंपनियों के लिए इन पदों की मंजूरी दे दी है.

वर्ष 2011 में बिजली कंपनियों की संगठनात्मक संरचना तय की गई थी, जिसमें महज कुल 28035 नियमित पदों को ही मंजूरी दी गई थी. ऐसे में बिजली कंपनियों में नियमित अधिकारियों-कर्मचारियों की पूर्ति के लिये संविदा और आउटसोर्स का रास्ता अपनाया गया, लेकिन संविदा और आउटसोर्स के कर्मचारियों की जवाबदेही कम होने के कारण शिकायतों का दौर बढ़ गया, जिससे कि बिजली कंपनियों की क्वालिटी सर्विस पर इसका असर पड़ा. सबसे बड़ी बात ये कि नये नियमित पदों 20118 तो लाइन मेन के पदों पर ही भर्ती होगी. इसके अलावा 211 सहायक यंत्री, 1339 जूनियर इंजीनियर और 8094 लाइन सहायक के पद शामिल हैं. दरअसल वर्ष 2011 में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 91 लाख थी, जो कि अब बढ़कर एक करोड़ 77 लाख तक जा पहुंची है. वहीं क्षमताएं भी लगभग दोगुनी तक हो गई है. वहीं नियमित पदों की संख्या लगातार कम हो रहे थे. वर्ष 2025 में तो नियमित पद कार्यरत अधिकारियों- कर्मचारियों की संख्या लगभग 16 हजार तक सीमित हो गई थी. मौजूदा समय में बिजली कंपनियों में कार्यरत संविदा और आउटसोर्स वाले कर्मचारियों की सेवाअवधि पूरा होने तक वे कार्यरत रहेंगे, इन पदों के रिक्त होने पर नियमित पदों गणना कर लगातार भर्ती का सिलसिला चलेगा. निर्णय के तहत बिजली कंपनियों में 17620 अनुपयोगी पद समाप्त होंगे,वहीं 5650 पदों को डाइंग कैडर घोषित किया गया है. यानी ये पद ही समाप्त कर दिये जाएंगे. नये पदों को भरने के लिये ऊर्जा विभाग को अधिकृत किय गया है.

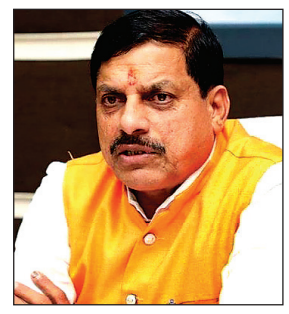

कैबिनेट ने प्रदेश के सभी किसानों की सिंचाई जलकर की राशि मे से ब्याज राशि माफ किए जाने का निर्णय लिया है. यदि किसान 31 मार्च 2025 तक की कुल बकाया राशि की मूल राशि 31 मार्च 2026 तक एक साथ जमा करते है तो ब्याज की राशि माफ कर दी जायेगी. इस तरह लगभग 84 करोड़ 17 लाख रूपये की ब्याज राशि शासन द्वारा माफ कर दी जायेगी. 31 मार्च 2025 की स्थिति में किसानों पर सिंचाई जलकर की अवशेष राशि 647 करोड़ 67 लाख रूपए बकाया है. जिसमे मूल राशि 563 करोड़ 29 लाख रूपए एवं ब्याज राशि 84 करोड़ 17 लाख रुपए है.

रिटायरमेंट के बाद प्राकृतिक खेती और वेदों का अध्ययन करूंगा

नयी दिल्ली, 09 जुलाई. अहमदाबाद. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को अपने रिटायरमेंट प्लान के बारे में बड़ी बात कही. केंद्रीय गृह मंत्री ने ये बात सहकारिता मंत्रालय के चौथे स्थापना दिवस के मौके पर गुजरात में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि मैंने तय किया है कि रिटायरमेंट के बाद अपना बाकी जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के अध्ययन को समर्पित करूँगा.

उन्होंने कहा कि यह खेती कोई परंपरागत पद्धति नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रयोग है, जिससे न केवल स्वास्थ्य लाभ होता है, बल्कि उत्पादन में भी वृद्धि होती है. सहकार संवाद कार्यक्रम के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान की महिलाओं और सहकारी संस्थाओं से जुड़े लोगों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने कहा, मैंने अपने खेत में यह पद्धति अपनाई है और अब अनाज उत्पादन में लगभग डेढ़ गुना बढ़ोतरी हो चुकी है. रासायनिक उर्वरकों से उत्पन्न खाद्यान्न खाने से कैंसर, ब्लड प्रेशर और थायरॉइड जैसी बीमारियाँ होती हैं. यदि लोग प्राकृतिक तरीके से उगाए गए अन्न का सेवन करें तो उन्हें दवाओं की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी.

वडोदरा में पुल ढहने से दस लोगों की मौत

40 साल पहले बना था पुल | **212** करोड़ रुपये की लागत से नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी थी | **02** लाख मृतकों के परिजनों को और घायलों को 50 हजार की सहायता

नयी दिल्ली 09 जुलाई. गुजरात के वडोदरा जिले में बुधवार सुबह एक पुराने पुल के ढहने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई कई लापता बताए जा रहें हैं. यह दुर्घटना सुबह करीब 7 से 7.30 बजे के बीच महिसागर नदी पर स्थित पुराने पुल पर हुई, जब कई वाहन पुल से गुजर रहे थे. पुल टूटने के कारण तीन ट्रक, दो इको गाड़ियाँ, एक रिक्शा, एक पिकअप और दो मोटरसाइकिलें नदी में गिर गईं. हादसे की पुष्टि जिला कलेक्टर अनिल धमेलिया ने की है.

घटना के तुरंत बाद स्थानीय नागरिकों, दमकल कर्मियों और राहत दलों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. मौके पर 20 से अधिक अग्निशमन कर्मी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें, दमकल गाड़ियाँ, नावें, एम्बुलेंस और चिकित्सा दल राहत कार्य में जुटे हुए हैं. कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है.

बताया जा रहा है कि यह पुल वर्ष 1985 में बनाया गया था और हाल ही में गुजरात सरकार ने 212 करोड़ रुपये की लागत से नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी थी. हादसे के बाद आणंद से वडोदरा, भरूच और अंकलेश्वर का सीधा संपर्क टूट गया है. सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, वडोदरा जिले में पुल ढहने से हुई जनहानि अत्यंत दुखद है. जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं. ईश्वर से प्रार्थना है कि घायल लोग जल्द स्वस्थ हों. प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है.

हमले के लिए आईईडी खरीदा ऑनलाइन

नयी दिल्ली, 9 जुलाई. आतंक की फंडिंग पर नजर रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था 'वित्तीय कार्रवाई कार्यबल' (एफएटीएफ) की नई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है. रिपोर्ट में आतंकवादी फंडिंग जोखिम पर समग्र अद्यतन के अनुसार, 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले में प्रयोग किया गया एल्युमिनियम पाउडर ई-कॉमर्स साइट अमेजन से खरीदा गया था. यह पाउडर विस्फोटक की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हुआ और इसका उपयोग अक्सर आईईडी और रॉकेट ईंधन बनाने में किया जाता है. रिपोर्ट में 2022 के गोरखनाथ मंदिर हमले का भी जिक्र है. इसमें बताया गया है कि हमलावर ने ऑनलाइन भुगतान सेवा 'पेपाल' के जरिए लगभग 6.69 लाख रुपये विदेश भेजे थे.

12 माओवादियों का आत्मसमर्पण

- साढ़े 28 लाख के नौ इनामी नक्सलियों ने डाले हथियार
- 241वीं वाहिनी सीआरपीएफ बस्तर की विशेष कार्रवाई

दंतेवाड़ा 09 जुलाई (वार्ता) छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बुधवार को साढ़े 28 लाख के नौ इनामी माओवादियों सहित कुल 12 माओवादियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया. इनमें एक माओवादी दंपति भी शामिल है.

इस अभियान के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों का आंकड़ा एक हजार पार करने के बाद दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक (एसपी) गौरव राय ने केक काट कर खुशी जाहिर की. माओवादियों को आत्मसमर्पण कराने में डीआरजी/ बस्तर फाईटर्स, आसूचना शाखा दंतेवाड़ा, आरएफटी (आसूचना शाखा) दंतेवाड़ा, 111वीं वाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) एवं 241वीं वाहिनी सीआरपीएफ बस्तर का विशेष योगदान रहा. आत्मसमर्पण करने वाले दो शीर्ष माओवादी नेताओं पर आठ-आठ लाख का इनाम घोषित था. इनमें चंद्रना - थाना गंगालूर क्षेत्र का सक्रिय माओवादी, डीकेएस एम/ पश्चिम बस्तर डिवीजन अध्यक्ष और अमित उर्फ हिंगा बारसा थाना जगरगुंडा क्षेत्र से, डीकेएसएम कंपनी नंबर 10 का सदस्य था. अन्य तीन नक्सली - हिड़मे कोवासी, जीबू उर्फ रोशन, और अनिल लेकाम निचले स्तर के सदस्य रहे, जिन पर कोई इनाम घोषित नहीं था.

अन्य इनामी नक्सली

अरुणा - पांच लाख (डीकेएसएम मेडिकल टीम सदस्य)
देवा कवासी - तीन लाख (लाइन नंबर 32 कमांडर)
राजेश मड़काम - दो लाख (बीजापुर अध्यक्ष, डीकेएसएम)
पायके ओयाम - एक लाख (परिया कमेटी पार्टी सदस्य)
कोसा सोढ़ी, महेश लेकाम, और राजू करटाम - 50-50 हजार रुपये

पीएम मोदी के विजन से आपदा प्रबंधन में बदलाव

बेंगलुरु, 9 जुलाई. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने कहा कि वित्तपोषण तंत्र, संस्थागत विकास और क्षमता निर्माण में निवेश का उद्देश्य मापनयोग्य परिणाम प्रदान करना है. डॉ. मिश्रा ने जोर देकर कहा कि भारत की विकसित होती आपदा जोखिम प्रबंधन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक आपदा-संबंधी मृत्यु दर में कमी है.

डॉ. पी.के. मिश्रा भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु में सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी (सीपीपी) के रजत जयंती स्थापना दिवस के अवसर पर संबोधित कर रहे थे. उन्होंने बताया कि कैसे एक व्यापक दृष्टिकोण वाले गुजरात भूकंप भरपाई कार्यक्रम ने देश की आपदा प्रबंधन प्रणाली को बदलने में मदद की.

डॉ. पी.के. मिश्रा ने इस बात पर जोर दिया कि बेहतर पूर्व-चेतावनी प्रणालियों, सशक्त संस्थानों, बेहतर योजना और अधिक संवेदनशील वित्तपोषण के संयुक्त प्रभाव से, तीव्र और धीमी शुरुआत वाले, दोनों ही प्रकार के खतरों में मृत्यु दर में लगातार गिरावट देखी गई है. डॉ. मिश्रा ने यह भी कहा कि यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क के तहत मूल प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिस पर भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है.

गुजरात से म्यांमार तक: पिछले 25 वर्षों में भारत की आपदा प्रबंधन नीति और कार्यप्रणाली का विकास विषय पर अपने व्याख्यान पर विस्तार से चर्चा करते हुए, डॉ. पी.के. मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के विजन से प्रेरित किया. उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले दो-तीन दशकों में भारत की आपदा प्रबंधन नीतियां और कार्यप्रणाली कैसे विकसित हुई हैं.

डॉ. पी.के. मिश्रा ने कहा कि भारत में आपदा जोखिम प्रबंधन की कार्यप्रणाली में कई बदलाव आए हैं. डॉ. मिश्रा ने अपने विचार-विमर्श में 1991 के ओडिशा सुपर साइक्लोन, 2001 के गुजरात भूकंप और 2004 के हिंद महासागर में आई सुनामी के बारे में बताया, जिससे कई सबक मिले. डॉ. मिश्रा ने कहा कि 1993 का लातूर भूकंप और 2005 का कश्मीर भूकंप जैसी अन्य घटनाएं भी हुईं.

17 सूत्रीय मांग | बंगाल, केरल और पंजाब में व्यापक प्रभाव, दिल्ली में जनजीवन सामान्य

भारत बंद का दिखा मिला-जुला असर

नयी दिल्ली, 09 जुलाई. केंद्र सरकार की नीतियों और श्रमिकों की 17 सूत्री मांगों के समर्थन में दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा आहूत भारत बंद का असर देशभर में मिला-जुला देखने को मिला. आयोजकों को उम्मीद है कि औपचारिक और अनौपचारिक रूप से इस हड़ताल में 25 करोड़ से ज्यादा मजदूर भाग लेंगे. जिनमें ग्रामीण भारत से किसान और खेतिहर मजदूर भी शामिल हो सकते हैं.

जहां पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, ओडिशा, तेलंगाना और बिहार जैसे राज्यों में बंद का खासा असर रहा, वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश और भाजपा शासित राज्यों में जनजीवन सामान्य बना रहा.

राजधानी दिल्ली में बंद को वाम संगठनों ने समर्थन दिया और जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन सामान्य जनजीवन प्रभावित नहीं हुआ. बाजार खुले रहे और यातायात सामान्य रूप से चलता रहा. इसके उलट पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों और उनसे जुड़ी ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर व्यापक बंद देखा गया. कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के कई जिलों में रेलवे पटरियाँ अवरुद्ध की गईं. पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई स्थानों पर झड़पें हुईं और 20 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया. एसएफआई के महासचिव सृजन भट्टाचार्य जादवपुर में प्रदर्शन के दौरान घायल हो गए. ओडिशा में भी बंद का आंशिक प्रभाव रहा. राजधानी भुवनेश्वर में पटरियों पर धरना दिया गया, हालांकि ट्रेन सेवाएं प्रभावित नहीं हुईं. पेट्रोल पंप और निजी बस सेवाएं ठप रहीं जबकि राज्य परिवहन की बसें चलती रहीं.

तेलंगाना में सिंगरेनी कोल फील्ड्स में श्रमिकों की एक दिवसीय हड़ताल के चलते उत्पादन ठप रहा. बिजली कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हुए. भूपालपल्ली डिवीजन में करीब छह हजार टन कोयले का उत्पादन प्रभावित हुआ.

पटना-दिल्ली इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग

नई दिल्ली, 9 जुलाई. पटना से दिल्ली जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट (6ई-5009) में बुधवार को उड़ान भरते ही बर्ड हिट की घटना हुई, जिसके बाद पायलट ने सतर्कता दिखाते हुए पटना एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग कराई. विमान में 169 यात्री सवार थे.

जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई. एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया, सभी यात्री सुरक्षित हैं. यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और वैकल्पिक उड़ानों की व्यवस्था की गई. इससे एक दिन पहले मंगलवार (8 जुलाई) को दिल्ली से पटना आने वाली फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिससे उड़ान करीब सात घंटे तक टल गई. नाराज यात्रियों ने हवाई अड्डे पर विरोध भी दर्ज कराया. फ्लाइट शाम छह बजे रवाना हो सकी. गौरतलब है कि 12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में 275 लोगों की जान गई थी. एयर इंडिया का विमान मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिरा था. मृतकों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे.